दैनिक

प्रातः कालीन

भारत सरकार से रजिस्टर्ड

हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र

क्यूँ न लिखूँ सच

मुरादाबाद से प्रकाशित

RNI NO- UPBIL/2021/83001

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए

9027776991

knlslive@gmail.com

KNLS Live

सम्पर्क करें-9027776991

न्यूज़ पोर्टल बनवाये 2999' में

न्यूज़ पेपर डिजाइन कराये कम दाम में

वर्ष :- 03 अंक :- 73 मुरादाबाद, 02 July 2023 (Sunday) पृष्ठ :- 12 मूल्य : 3.00 रुपये

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

'नियत में खोट और गरीब पर चोट', जनता से पीएम

मोदी की अपील; विपक्षियों की गारंटी से रहें सतर्क

शहडोल, ऑनलाइन डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन एवं 3.5 करोड़ पीवीसी आयुष्मान वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शहडोल के लालपुर में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालपुर में आयोजित वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लालपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लालपुर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन एवं 3.5 करोड़ पीवीसी आयुष्मान वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मुझे रानी दुर्गावती जी की इस पावन धरती पर आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन अभियान की शुरुआत हो रही है। आयुष्मान कार्ड उन्होंने कहा कि आज ही मध्य प्रदेश में एक करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन दोनों ही प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गोंड समाज, भील समाज और अन्य हमारे आदिवासी समाज के लोग ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज शहडोल की इस धरती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई-बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चों और उनके परिवारजनों के जीवन बचाने का संकल्प है।

मुक्ति अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान की यात्रा के दौरान नोबल पुरस्कार विजेता विज्ञानी से मुलाकात की। मुझे पता चला कि वह विज्ञानी सिकल सेल एनीमिया को लेकर बहुत काम कर चुके हैं। ऐसे में मैंने उनसे सिकल सेल एनीमिया के इलाज में मदद मांगी। साथियों सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का अभियान %अमृत काल% का प्रमुख मिशन बनेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा यानी 2047 तक हम सब मिलकर एक मिशन मोड में अभियान चलाकर इस सिकल सेल एनीमिया से अपने आदिवासियों और देश को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया का पता लगाने के लिए जांच और स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। जांच नहीं कराने पर लंबे समय तक लोगों को इस बीमारी के बारे में मरीज को पता न चले।

सरकार का प्रयास, कम हो बीमारी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2013 में मलेरिया के 10 लाख मामले थे, 2022 में यह भी घटते-घटते दो लाख से कम हो गए। 2013 में कुष्ट रोग के सवा लाख मरीज थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 70-75 हजार रह गई। पहले दिमागी बुखार के कहर के बारे में भी हम सब जानते थे। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में इसके मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, जब बीमारी कम होती है तो लोग भूख, पीड़ा, संकट और मृत्यु से भी बचते हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो। साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो। इसी वजह से हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं। जिससे लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ। %मोदी की गारंटी कार्ड% प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में एक करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। अगर किसी को अस्पताल जाना पड़ा तो यह कार्ड उसकी जेब में पांच लाख रुपये के बराबर होगा। यह कार्ड दिखा देना यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच करोड़ गरीबों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होता तो इन लोगों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करके बीमारी का उपचार करना पड़ता। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के जितने मामले होते हैं, उनमें से आधे अकेले हमारे देश में होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 वर्षों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया, लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब हमारी सरकार ने उठाया है। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है।

झूठी गारंटी देने वालों से रहें सावधान

उन्होंने जनता से आग्रह किया कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की अपनी गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई-नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे कोड को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भाप लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देने का मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त के सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन देने की बात करते हैं तो समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा।

नियत में खोट और गरीब पर चोट

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब- नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही उनके खेल हैं। वो 70 साल में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है और उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,इन झूठी गारंटी देने वालों का रवैया हमेशा से आदिवासियों के खिलाफ रहा है। पहले जनजातीय युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनौती आती थी, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है, लेकिन झूठी गारंटी देने वाले एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई-बहनों के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएं। क्रू ने वीरांगना रानी दुर्गावती को किया नमन- प्रधानमंत्री मोदी ने लालपुर में आयोजित वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लालपुर में एक जनसभा को संबोधित किया।

कांग्रेस पर बरसे ष्टरू शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी का जबलपुर में भव्य स्मारक बनाया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बांटे जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना वरदान है, लेकिन कांग्रेस ने गरीबों के अधिकार छीनने का काम किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने हमारी बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की बहनों को मिलने वाले एक हजार रुपये रोक दिये थे, लेकिन हमने राशि देना पुनः प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के साथ धोखा किया।

योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि पर भारत सरकार ने दी बधाई, एक नल-एक पेड़ अभियान का शुभारंभ

यूपी सरकार ने प्रदेश के 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचा दिया है। नल से कनेक्शन देन के मामले में महोबा जिला नंबर वन है। इस पर भारत सरकार के अधिकारियों ने योगी सरकार की प्रशंसा की है। यूपी में जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने शनिवार को ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का 50 फीसदी आंकड़ा पार किया। प्रधानमंत्री के विजन पर मिशन की तरह कार्य कर रही योगी सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के आधे सफर को पूरा करते हुए प्रदेश के 1,33,25,752 ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचाने की उपलब्धि हासिल की है। अब तक करीब 7,99,54,512 ग्रामीणों को योजना के लाभ से जोड़ दिया है। बता दें कि हर घर जल योजना से वर्ष 2024 तक 2 करोड़ 66 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल प्रदान किया जाना है। भारत सरकार के अधिकारियों ने तेजी से लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रही योगी सरकार की इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी है।

नल कनेक्शन देने में बुंदेलखंड का महोबा नम्बर वन

योगी सरकार की इस उपलब्धि में बुंदेलखंड और विन्ध्य के 9 जिलों के दूरस्थ इलाके भी शामिल हैं। बुंदेलखंड के सात जिलों में हर घर जल योजना से करीब 11,78,927 ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ पेयजल की धार पहुंच रही है। नल कनेक्शन देने के मामले में बुंदेलखंड का महोबा जिला नम्बर एक पर है। महोबा में 91.88 फीसदी ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचा दिया गया है। विन्ध्य में भी योजना से 4,74,244 ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। पूर्वांचल के 27 जिलों में 80,26,883 ग्रामीण परिवारों के कुल 4 करोड़ 81 लाख से अधिक ग्रामीणों तक हर घर नल से जल पहुंच रहा है। इसी प्रकार से पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में योजना से 63,28,887 ग्रामीण परिवारों को जीवन मिशन की हर घर जल योजना से स्वच्छ जल की सौगात मिल गई है।

एक नल-एक पेड़ अभियान का शुभारंभ

वहीं मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर से प्रदेश में 1 से 7 जुलाई तक चलने वाले एक नल-एक पेड़ अभियान का शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस दौरान पौधरोपण के साथ जल समिति की महिलाओं व नल कनेक्शन दिए जाने वाली ग्रामीण महिलाओं को उपहार स्वरूप पौधे भेंट कर 'एक नल एक पेड़' कैंपेन का शुभारंभ किया गया। बता दें कि 1 से 7 जुलाई तक राज्य में करीब 5 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के साथ पौधा रोपण भी किया जाएगा।

ट्विटर पर छाया रहा #UPTreeForTap

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा यूपी में 50 फीसदी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने और एक पेड़-एक नल अभियान के शुभारंभ अवसर पर ट्विटर पर #UPTreeForTap छाया रहा। इस ट्वीट के पक्ष में जमकर ट्वीट, रिट्वीट और लाइक किये गये। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए इस हैशटैग पर राज्य सरकार को बधाईयां दीं।

संपादकीय Editorial

fatal debris treatment

When the debris of development started staring, it seems to be becoming a big issue legally. The four-laning from Kiratpur to Nerchowk has discovered the milestones of centuries, but along with the economic meaning of such connectivity, some geographical conditions are also attached and while explaining these, the Hon'ble High Court has asked the concerned department that after all, the debris What are his arrangements? On the complaint of the Forest Department, the NHAI had paid the fine for dumping the debris in the forest, but the court is looking beyond the reality of the fine and asking that the real answer will be found only by permanently disposing the debris. Undoubtedly, a case has come before the court regarding the debris of a four-lane, but it is an important question related to the ongoing development in the entire state. Due to more or less every road, power project, urbanization, residential construction and state activities, the geographical conditions of Himachal are creating so much debris that we have to plan for its scientific disposal as well as its dumping. In a state where the management of garbage disposal has also become a disaster, the debris associated with every construction can be even more fatal. Many years ago due to various power projects in Chamba, the flow of Ravi was causing problems. Similarly, due to the rain debris, water drainage has started taking a terrible form.

Large dams and small watershed projects have contained so much silt or debris within them that it has completely blocked the natural channels of water storage or water percolation. In this perspective, due to water power, electricity and PWD itself, debris of all kinds of development is standing on the side of the roads. The Forest Department may raise the neck of environmental messages in the tradition of Van Mahotsav, but the destruction of its debris till human settlements is no less culpable. In such a situation, Himachal's innovation will be organized only with the cooperation of the Forest Department. Needless to say that maximum projects for streamlining urban development are stuck in forests. The most dangerous aspect is also that due to the hindrances of the Forest Department, the solid waste management of the cities is not taking a definite shape.

In this regard, if many projects of waste disposal remain stuck in the stubborn and wasteful process of the Forest Department, then destruction is certain. Rural and urban development plans of public and private activities of development in the state should be coordinated in such a way that we can solve the challenges of the next century. Somewhere the pressure of geographical needs seems to be entangled with its own darkness.

According to law, every city and even every village will have to decide dumping areas in future. These areas will not be acquired from normal land, but from forest land only. That is, somewhere a four-lane or power project is being built, then according to this land will have to be made available to the dumping ground from the forest department's land. If every city prepares dumping ground under future monitoring, then in the coming years these places can be used as an alternative to public needs. It is obvious that due to the planning and magnanimity of the Forest Department, with the consciousness of which the evil debris of Fourlane came to the fore, its scientific disposal will also be done. The state's dependence on forest land will increase in the shape of Himachal's future, human activities and development, it would be better if Himachal's geographical, social and existence issues are sought back from the forests so that development does not become blind.

Uniform Civil Code: Why so much hue and cry even before a draft is out?

Interestingly, there is not much justification for supporting and opposing the implementation of UCC in the country at present because no basic format has been brought forward. The Law Commission of the country has issued a notification on June 14 seeking public opinion on the UCC. Prime Minister Narendra Modi on June 27 at the BJP's booth expanders' conference in Bhopal announced the Uniform Civil Code (UCC) in the country. Raised the issue of implementation, it became clear that this is the core issue for the party for the Lok Sabha elections to be held next year. The BJP hopes to polarize voters on this issue on the same lines as it did on the issue of Ram Mandir or the abrogation of Article 370 in Kashmir. On the other hand, the opposition parties are also trying to assess the political edge of this issue. This is the reason why his response to this issue has been wary yet hostile.

Interestingly, there is not much justification for supporting and opposing the implementation of UCC in the country at present because no basic draft has been brought before the country. Only the Law Commission of the country has issued a notification on June 14 seeking public opinion and suggestions on the UCC. It is said that various organizations and individuals, including the Muslim Personal Law Board, have given more than eight and a half lakh suggestions to the Commission. This matter also seems a bit different because usually in any case, opinions or objections are invited on it only after the issuance of any document or draft. But it seems that on the basis of the suggestions received, the Law Commission will probably prepare a base letter or draft. What will happen next, the situation will be clear after July 14. But a tussle has started in the political parties regarding this proposed UCC, in which questions are being raised about the intention of the Modi government and its commitment to the Constitution. On the other hand, the Modi government and the BJP are invoking the Constitution itself and saying that the Uniform Civil Code is being brought in accordance with the spirit of the Constitution and this is the need of the hour.

There is no doubt that the Uniform Civil Code is mentioned in the Indian Constitution. But in Article 44 of the State Policy Directive in Part 4 of the Constitution, the framers of the Constitution have mentioned it in just one sentence. According to which (according to the authorized Hindi translation of the Constitution) 'The State shall endeavor to obtain a Uniform Civil Code for the citizens throughout the territory of India.' That is, it is not mandatory to do so, but the State (Government) shall endeavor to do so . One of the reasons for this was that even in the Constituent Assembly debates on UCC, Muslim representatives had opposed making it mandatory, whereas fundamental rights have been considered essential. This means that the framers of the Constitution agreed in principle that a Uniform Civil Code is desirable in a culturally and religiously plural country like India, but it would be appropriate to implement it only after overall consideration and consensus. The reason for this is that there may be a penal code for crimes in this country, but the socio-religious rules and regulations are different for each religion and generally people consider it necessary to follow them. The interference of any other element in this is considered unnecessary. There are some anomalies in these laws as well, but due to religious urges and traditional beliefs, people do not want to change or leave them. However, due to education and other reasons, some changes are visible at different levels in different societies. Why so much ruckus about UCC?- Now the question is that if the idea of Uniform Civil Code is constitutional, then what is the harm in implementing it or even having such an idea?

Since there is no draft in front of anyone in this regard, all the opposition and support are more on the basis of guesses and apprehensions. The first opposition is to change or abolish the personal laws applicable in a particular religion or society. That is why voices of opposition to UCC are being raised from Muslims, Sikhs and some other religions. Initially, there was a lot of bitterness in this protest, but now it seems that despite political insistence, this protest is taking some logical form of bigotry. Therefore, all the opponents and objectors are going to put their point in front of the Law Commission in a legal way, which is also a right way. Given the things that are coming out, or the countries where this code is in force, it can be understood that the UCC will focus on some fundamentals, such as the minimum age of marriage, the procedure related to divorce, the right to adopt, Alimony, polygamy or polyandry system, inheritance, succession and family planning etc. Some laws related to these are also applicable in different states. In the Uniform Civil Code, the same law will apply to people of all religions regarding these issues. In other words, once the UCC is implemented, the already applicable personal laws of different religions will end. Such as Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Indian Christian Marriage Act, Indian Divorce Act, Parsi Marriage and Divorce Act etc. However, Muslim personal law has not been codified. This law is based on their religious books. But Muslims feel that implementation of UCC will interfere in Shariat, which they will never accept. UCC is already applicable in Goa- The interesting thing here is that Goa is the only state in the country where UCC is applicable. 8.33 percent Muslims live in Goa. Lake So far he has not had any problem with UCC. No one went to court against him. That is, they are following their religious customs strictly. Whereas in Goa, this law has been in force since 1867, from the time of the Portuguese rulers. This means that there are more skeptics than skeptics about the UCC. However, the Sikh society has also expressed apprehension. According to the Akali Dal, the UCC may affect their 'Anand Karaj' (Sikh marriage system). On the other hand, the Buddhist community is also demanding recognition of the Buddhist marriage system as separate from the Hindu marriage system. There are many questions in the minds of people regarding UCC – there is also a doubt that the government can impose Hindu social religious laws on other religions under the guise of UCC. This is not possible because Hindus themselves may have to keep some of their rules and traditions on hold for the sake of UCC. Prominent in this is the Hindu Undivided Family (HUF). AIMIM leader Asaduddin Owaisi surrounded PM Modi on this issue and asked whether he will abolish HUF? It is said that through this in the country, Hindu families earn Rs 3 thousand crore every year. HUF is treated as a separate entity under the Income Tax Act. Now daughters also have a share in the family property and under this they get some exemption from tax liabilities. Although the joint family system is now very less among the Hindus, it has been replaced by the unit family system. This means that except for a few selected laws, all religions will continue to have their own customs and traditions. But having different laws in such cases may put some curb on the ongoing litigation. Now the real question is why is the Modi government raising this issue now? If the government wanted, it could have brought it in the first or second year of Modi 2.0 itself. But he didn't do that. However, the debate on this issue started in December last year with the introduction of a private member's bill by BJP MP Kirodilal Meena in the Rajya Sabha for the implementation of the Uniform Civil Code. This bill had the support of the BJP. For the BJP, this issue is from the days of the Jana Sangh. After the formation of BJP, the issues on which the party has been growing in the 90s are the removal of Article 370 in Kashmir, the construction of Ram temple in Ayodhya and the implementation of Uniform Civil Code in the country. Two of these have been completed, only the issue of UCC remains. On the other hand, the Law Commission had also created a sensation in 2018 by seeking opinion on UCC, but after opposition from some sections, it itself withdrew this initiative saying that at present it is not needed in the country.

Need of UCC country? - But before the 2023 elections, the Modi government and the Law Commission have started feeling that now UCC is needed in the country. There is also a sense of 'unity in diversity' behind it, but in a different way. Some people believe that the Uniform Civil Code will strengthen the secular character of the country. Perhaps for this purpose the Prime Minister said that the 'one country and two laws' system cannot work. The party once used to give a similar slogan 'One country, two legislations, two leaders and two symbols' about Jammu and Kashmir. But will the issue of UCC cook like 'Ram Mandir' in the furnace of votes? Will the voters and especially the majority community feel the same emotional connect with the UCC issue as it did in the case of the Ram Mandir? Because the issue relates to uniform codification of various socio-religious customs and is more of a legal one. Converting this into vote mobilization is not easy. There will be polarization of voters regarding UCC, but how much, it is very difficult to say and it would be political naïveté to assume that other ground issues and responsibilities will be buried in front of this issue. For the polarization of votes, it is necessary that the draft should come out first, so that the nature of the proposed Uniform Civil Code can be clarified and people can form an opinion in its favor and against. It is not yet clear when this draft will come. Although there is news of UCC draft prepared based on 15 points in the state of Uttarakhand, which has promised to implement UCC first, but it has not been made public yet. It is possible that the Law Commission may consider it as the basic draft. But if the commission has received more than eight and a half lakh suggestions, it will take a long time to study them and incorporate them in the draft (if that happens). It is unlikely that this work will be completed before the next Lok Sabha elections. Even if a draft is brought in haste, it is bound to create a ruckus. Elections will also be held in the same hall. This means that there are still many hurdles in converting UCC into law. The effort is to maintain the atmosphere, which is happening.

रैली निकालकर विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान का किया आरंभ

मुरादाबाद-सीएमओ कार्यालय पर फीता काटकर और गुब्बारे उड़ाकर जिलाधिकारी ने अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया रैली को दिखाई हरी झंडी, शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को जागरूकता एक से 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का आरंभ शनिवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सीएमओ कार्यालय पर किया। उन्होंने प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी डा. विश्राम सिंह, डिप्टी सीएमओ डा. संजीव बेलवाल के साथ फीता काटकर और गुब्बारे उड़ाकर जिले में अभियान शुरू किया। उन्होंने चिकित्साधिकारियों के साथ नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को समन्वय कर लोगों को संचारी रोगों डेंगू, मलेरिया आदि से बचाने के लिए काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मानसून के समय बारिश के बाद जलभराव से मच्छरों के पनपने से संचारी रोग तेजी से बढ़ते हैं। प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि विशेष अभियान में घर-घर जाकर टीमें लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगी। जिला मलेरिया अधिकारी पीएन यादव ने बताया कि महानगर में नगर निगम की ओर से हाईरिस्क वाले मोहल्लों में विशेष रूप से सफाई अभियान चलाकर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाएगा। झाडियों की कटाई कराकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा। एक से 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान को सभी की सहभागिता से सफल बनाया जाएगा। जागरूकता रैली में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर के विभिन्न मार्गों से होकर लोगों को संचारी रोगों के बारे में जानकारी दी।पंफलेट वितरित कर लोगों को बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि अभियान में ओआरएस का घोल और जिंक की गोली का वितरण किया जाएगा। आशाओं के अलावा मलेरिया विभाग के फील्ड वर्कर शहर और गांवों में मच्छर न पनपें इसके लिए लोगों से साफ पानी का जमाव न करने, कूलर का पानी बदलते रहने, फ्रिज की आइस ट्रे को नियमित साफ करने और छत या घर के बाहर पड़े पुराने टायरों, बर्तनों को हटाने या उन्हें ढक कर रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिससे डेंगू और मलेरिया न फैले। स्कूलों में प्रार्थना सभा के अलावा आसपास के क्षेत्र में रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। गोष्ठी और चित्रकला के माध्यम से जागरूकता बढ़ाया जाएगा।

प्राप्त 23 जनशिकायतों में से कई प्रकरणों का मौके पर निस्तारण

मुरादाबाद-जिलाधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सदर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सम्पन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवसों में आने वाली जनशिकायतों का समयान्तर्गत व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्पूर्ण समाधान में दिवस आवेदकों द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रेषित किए जायें उनमें आवेदक का अथवा उसके किसी परिचित का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रुप से दर्ज किया जाये। प्रार्थना पत्र दर्ज होने के पश्चात् सम्पूर्ण समाधान दिवस में आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाये। आवेदन कर्ता की सुनवाई कर उसका तत्काल निस्तारण करने का यथा संभव प्रयास करना सुनिश्चित करें। समस्त अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने से संबंधित प्रार्थना पत्रों को उसी दिन प्राप्त करने के बाद ही तहसील कार्यालय छोडे। इसके साथ ही आवेदन पत्रों की प्राप्ति की पूरी व्यवस्था संबंधित तहसीलदार की देखरेख में की जाएगी तथा सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजन के बाद उसी दिन सभी प्रार्थना पत्रों का कम्प्यूटर पर अंकन कराना भी संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र का कम्प्यूटरीकरण (स्कैनिंग, अपलोडिंग एवं विवरण फीडिंग) समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) (jansunwai.up.nic.in) से संबंधित सम्पूर्ण समाधान दिवस के पोर्टल पर किया जायेगा। शिकायती प्रार्थना पत्र पर अपेक्षित निस्तारण कार्यवाही व प्रगति की स्थिति भी संबंधित अधिकारी द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर समय-समय पर अपलोड की जाएगी। जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण एवं अनुश्रवण के संबंध में निर्देशित किया है कि निजी भूमियों का सीमाकंन/पैमाइश, निजी भूमियों का अविवादित नामान्तरण, खतौनी में नाम व अन्य अशुद्धियों का शोधन, फर्जी बैनामें के आधार पर नामान्तरण/कब्जा, संबंधित शिकायतों को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित लेखपाल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण किया जाये। राजकीय एवं सार्वजनिक उपयुक्त भूमियों यथा चकरोड, रास्ता, तालाब, खलिहान, नाली, चारागाह आदि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे, निजी भूमियों पर अन्य भूमिधरों/सहखाते द्वारा अवैध कब्जा, पट्टे की भूमि पर कब्जा, आबादी भूमि में पानी का निकास व आवागमन अवयुक्त करने संबंधी शिकायतों का तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित थाने के हेड कांस्टेबल की टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जाये। गृह विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रकरण संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को सन्दर्भित कर दिया जाए तथा सामाजिक न्याय, विकास एवं अन्य विभाग से संबंधित शिकायतों को खण्ड विकास अधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं अथवा यथावाश्यक टीम बनाकर मौके पर भेजकर निस्तारण कराया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों में से कम से कम 5 महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील शिकायतों को चिन्हित कर उनके निस्तारण हेतु मौके पर भेजकर उसी दिन निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाये। आज तहसील सदर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा अन्य शिकायतों को जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को समयान्तर्गत निराकरण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रोड के गड्ढों को दुरस्त किया जाये, पेंशन जारी करने तथा पूर्ति विभाग को नियमानुसार राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। राजस्व विभाग के अर्न्तगत भूमि संबंधी विवादों सहित विद्युत विभाग से संबंधित बिलों में गडबडी, राशन कार्ड बनाने की मांग आदि शिकायतें प्राप्त हुई। सम्पूर्ण समाधान दिवस मे जिलाधिकारी के निर्देशानुसार शिकायतें संबंधित विभागीय अधिकारियों को निश्चित समय सीमार्न्तगत निस्तारण करने के निर्देश के साथ सन्दर्भित की गयी। सम्पूर्ण समाधान दिवस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा, उपजिलाधिकारी सदर परमानंद, तहसीलदार सदर, पुलिस क्षेत्राधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य विभागो के जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

ब्लैक स्पॉट पर बचाव नहीं, हाईवे पर डेढ़ किमी के बीच में चार अवैध कट

मुरादाबाद-जीरो प्वाइंट से पेट्रोल पंप के सौ मीटर आगे तक हाईवे पर हैं अवैध कट, खतरे के बीच निकलते बाइक सवार मुरादाबाद-रामपुर हाईवे पर डेढ़ किलोमीटर के बीच की दूरी में चार अवैध कट हैं। इन अवैध कट से दिन में कई बार खतरा उठाकर बाइक सवार हाईवे क्रॉस करते हैं। हाईवे के आसपास घनी आबादी है लेकिन, सर्विस लाइन भी नहीं बनी है। वहीं, रामपुर दोराहा ब्लैक स्पॉट है। आए दिन यहां हादसे होते हैं लेकिन, इस दोराहा पर कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा है या अन्य कोई उपाय नहीं किए गए हैं। जिससे हादसों को रोका जा सके। दोराहे पर स्थित होटल के कर्मी मोइज आलम ने बताया कि रमजान से पहले गोद में बच्चे को लेकर पैदल निकल रही महिला को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इसमें महिला के पैर में चोट आई थी और उसके बच्चे का सिर ट्रक के टायर के नीचे आ गया था। इस तरह दोराहे पर आए दिन हादसे होते हैं। मोइज आलम ने कहा, दोराहा काफी खतरनाक है। यहां पर जिम्मेदारों को हादसे रोकने वाले कुछ उपाय करने चाहिए। वैसे दोराहे पर प्रचार वाले पोस्टर व होर्डिंग्स का अभाव नहीं है। दोराहे पर कोई खूबसूरती भी नहीं है, वैसे यहां

बीच में गोलाकर बाउंड्री बनाई गई है। यहां ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लाइट का भी इंतजाम है पर ये लाइटें काम नहीं करती हैं। इन्हीं लाइटों के नीचे खंभे में %%दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र धीरे चलें%% का बोर्ड जरूर लगा है, जो जीर्णशीर्ण हालत में है। हाईवे पर अवैध कट के स्थल मुरादाबाद जीरो प्वाइंट से रामपुर की ओर चलने पर रॉयल रानी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप तक तीन अवैध कट हैं। एक तो पेट्रोल पंप के ठीक सामने और दूसरा उसके करीब 100 मीटर आगे एक फैक्ट्री के सामने है। इस तरह कुल चार अवैध कट हैं। जिले में रामपुर हाईवे पर चार ब्लैक स्पॉट लपतपुर टोल प्लाजा प्रबंधक योगेश चौधरी ने बताया कि रामपुर हाईवे पर मुरादाबाद जिले में कुल चार ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं। इसमें पहला तो मुरादाबाद जीरो प्वाइंट ब्लैक स्पॉट है। फिर राजेड़ा चौराहा, मनकरा कट तिराहा और एक अन्य स्थल है। मुरादाबाद जीरो प्वाइंट से बाईपास बन चुका है। मुरादाबाद की तरफ आने वाली सड़क एनएचएआई में नहीं है। इसे पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर होना है लेकिन, पीडब्ल्यूडी के अभियंता चार्ज में ले नहीं रहे हैं। मुरादाबाद-काशीपुर हाईवे पर रामपुर दोराहे ब्लैक स्पॉट है। यहां दोराहे पर दुर्घटना से बचाव कार्य के संबंध में जानकारी करेंगे। रही बात मुरादाबाद जीरो प्वाइंट से रॉयल रानी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप तक करीब एक-डेढ़ किमी के बीच में हाईवे पर अवैध कट की तो इसकी मरम्मत के लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है।-अनुज जैन, पीडी-एनएचएआई

हाड़ों में हो रही बारिश से उफान पर रामगंगा, 188.27 मीटर जलस्तर

मुरादाबाद-हरिद्वार में कल से अधिक रहा गंगा का जलस्तर, मुरादाबाद में भी निगरानी बढ़ी, रामगंगा नदी कालागढ़ में 400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से जहां हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर गुरुवार से अधिक शुक्रवार को रहा। वहीं मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा नदी कटघर रेलवे पुल जलस्तर 188.27 मीटर रहा। जो चेतावनी स्तर 190.60 मीटर से सिर्फ 2.33 मीटर नीचे है। इसको देखते हुए बाढ़ कंट्रोल रूम से रामगंगा और गागन नदी के जलस्तर पर निगरानी बढ़ाते हुए राहत

व बचाव के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं।गुरुवार को हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 291 मीटर रहा। जो शुक्रवार को बढ़कर 291.15 मीटर होने से जलस्तर बढ़ते क्रम में नापा गया। यहां अपस्ट्रीम में 43047 और डाउनस्ट्रीम में 33396 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं रामगंगा नदी कालागढ़ में 400 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। हालांकि यहां की बजाय कटघर रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर चढ़ते क्रम में रहा। बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, उसके प्रभाव को कम करने और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कलेक्ट्रेट सभागार के द्वितीय तल पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय में बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। आपदा प्रबंध कार्यालय में सक्रिय कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर प्रशासन ने जारी किया है। इसके प्रभारी डिप्टी कलेक्टर प्रबुद्ध सिंह हैं। इसमें 15 जुलाई तक रोस्टरवार ड्यूटी लगाई गई है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उसमें चकबंदी विभाग के लेखपाल विकास का मोबाइल नंबर 6395106060 है। यह एक से 15 जुलाई तक सुबह छह बजे से दोपहर 2 बजे तक तैनात रहेंगे।

जबकि इनके साथ कृषि विभाग के आकाश कुमार का मोबाइल नंबर 8191068955 है। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे चकबंदी लेखपाल रामकुमार की तैनाती रहेगी। उनका मोबाइल नंबर 9917035184 है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व युगराज सिंह का कहना है कि प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम के पर्यवेक्षण में बाढ़ कंट्रोल रूम सक्रिय है। जो भी सूचना मिलेगी उसे शिकायत रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा। नदियों के गेज की सूचना दूरभाष पर प्राप्त कर दैनिक गेज रजिस्टर पर अंकित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ कंट्रोल रूम के नंबर 0591-2412728 और मोबाइल नंबर 9454416867 व टोल फ्री नंबर 1077 पर सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। जिला आपदा विशेषज्ञ पंकज कुमार मिश्रा इसमें सहयोग करेंगे। जिला आपदा विशेषज्ञ ने बताया कि जिले में 34 बाढ़ चौकियां और 22 बाढ़ शरणालय प्रशासन की ओर से चिह्नित किए गए हैं। जिला मुख्यालय के अलावा तहसील स्तर पर भी बाढ़ कंट्रोल रूम सक्रिय है। सदर तहसील में 0591-2971370, कांठ में 0591-2974411, बिलारी में 0591-270011 और ठाकुरद्वारा में 0591-2241231 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

सुपर जोइनिंग वीक

उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड,छतीसगढ़ पंजाब का तेजी से बढता आपका अपना

दैनिक क्यूँ न लिखूँ सच & KNLS Live

आवश्यकता है भारत के सभी राज्यों से

रिपोर्टर,विज्ञापन प्रतिनिधि की

12 पेज का फुल अखबार

एक बार कॉल अवश्य करे

9027776991

प्रसारित क्षेत्र - उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड,छतीसगढ़ पंजाब बाकि राज्यों से जल्द प्रसारित

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991

RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

बिहारपुर पहुंचे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अजय गोयल किया जनसंपर्क

भाजपा मण्डल बिहारपुर में पोलिंग बूथ में घर घर जनसंपर्क किया गया

रामचंद्र जायसवाल
क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर-बिहारपुर- प्रदेश भाजपा के आवाहन पर नेता और कार्यकर्ता मोदी सरकार के 9 वर्ष बेमिसाल कार्यक्रम के तहत किए गए कार्य को लोगों तक बैनर पोस्टर पंपलेट के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है सरगुजा संभाग के कार्यक्रम के सह प्रभारी एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गोयल भाजपा मंडल बिहारपुर में पोलिंग बूथ पर घर घर पहुंच कर जनसंपर्क किया उन्होंने कहा कि केंद्रीय कि मोदी सरकार ने गरीबों के हित के लिए लगातार काम कर रही है इसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है साथ ही किसानों के पास भी सोसाइटी में जाकर उनकी समस्या को सुनी संगठन में एकजुटता से

काम करने की आह्वान किया संगठन को पोलिंग बूथ पर कैसे मजबूत किया जाए इस पर विस्तार से चर्चा किए इस दौरान मंडल के सह प्रभारी शिव प्रसाद सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराम सोनी मंडल अध्यक्ष रामेश्वर बैस पूर्व मण्डल अध्यक्ष रामपाल जायसवाल ,विस्तारक विषकन्ठ प्रधान, महामंत्री हंसलाल जायसवाल,महामंत्री मुकेश कुमार साकेत,पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष कालीचरण कांशी,भाजयुमो महामंत्री विपी जायसवाल लक्ष्मण जायसवाल,बूथ अध्यक्ष मुकुंद लाल जयसवाल देवेन्द्र कुमार गुप्ता शिवसरन गुप्ता, लालमन सिंह सुरेंद्र पुरी,दीपक गुप्ता राम सजीवन पण्डो,आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सामग्रीयों की दर आमंत्रित

रामचंद्र जायसवाल-क्यूँ न लिखूँ सच

सूरजपुर- आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आपके फर्म से संबंधित सामग्रियों की सूची भेजी जा रही है। जिसका प्रतिदिन का दर अंकित कर 07 जुलाई 2023 तक बंद लिफाफे में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। ताकि उक्त दर से कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर छत्तीगढ़ से अनुमोदन ली जा सके। सामग्रियों की सूची इस प्रकार है। विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु विद्युत सामग्री का विवरण ट्यूब लाइट सेट कम्प्लीट 40 वॉट वायरिंग सहित प्रति नग प्रतिदिन, सी.एफ.एल. होल्डर सहित 85 वॉट प्रति नग प्रतिदिन, सी.ए.एल. होल्डर सहित 20 वॉट प्रति नग प्रतिदिन, मेटल हेलाईट फिटिंग सहित कम्पलीट 250 वॉट प्रति नग प्रतिदिन, मेटल हेलाईट फिटिंग सहित कम्पलीट 400 वॉट प्रति नग प्रतिदिन, हैलोजन फिटिंग 1000 वाट प्रति नग प्रतिदिन, हेलोजन फिटिंग 500 वॉट प्रति नग प्रतिदिन, पी.वी.सी. वायर 10 वर्ग मि.मी. सिंगल कोर प्रति मीटर कम्प्लीट प्रोग्राम, पी.वी.सी. आर्मरड/आर्मर्ड केबल 10/16 वर्ग मि.मी. 4 कोर प्रति मीटर कम्प्लीट प्रोग्राम, पी.वी.सी. आर्मरड/अन आर्मर्ड केबल 10/16 वर्ग मि.मी. 4 कोरप्रति मीटर कम्प्लीट प्रोग्राम, कम्प्यूटर बोर्ड (3 स्वीच 3 साकेट 1 पावर प्लग सहित) आर्थिंग वायर सहित प्रति नग प्रतिदिन, कटआउट कम्प्लीट 63 एम्पीयर/415 वोल्ट लकड़ी बोर्ड सहितप्रति नग प्रतिदिन, विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु माईक शामियाना, डेकोरेशन व अन्य का विवरण 2 साउण्ड बॉक्स, 2 एम्प्लीफायर, डिस्ट्रीव्यूटर, 2 कॉडलेस माईक व माईक स्टैण्ड 4 बैटरी हाईरिंज कम्प्लीट सेट प्रतिदिन, एम्प्लीफायर 1 नग एवं माइक्रोफोन सहित लाउडस्पीकर 2 नग, बॉक्स 2 नग बैटरी सहित (छोटा सेट) प्रतिदिन, 2 चोंगा 1 बैटरी, 1 एम्प्लीफायर माईक स्टैण्ड प्रतिदिन, जनरेटर 7.50 केव्ही (तेल सहित) प्रतिनग प्रतिदिन, ऑडियो कैसट एडिटिंग सहित प्रति कैसेट, गाड़ी में चोंगा, 1 एम्प्लीफायर 50 वॉट, 1 माईक, बैटरी 12 वोल्ट प्रतिदिन, एम्प्लीफायर 1 नग एवं माइक्रोफोन सहित लाउडस्पीकर 2 नग, बॉक्स 2 नग बैटरी सहित (छोटा सेट) प्रतिदिन, पोडियम/पण्डाल निर्माण आदि शामियाना 15×15 प्रतिदिन, शामियाना 15×20 प्रतिदिन, शामियाना 15×30 प्रतिदिन, शामियाना 20×30 वाटर प्रुफ प्रतिदिन , कनात, प्रतिदिनदर्री छोटी प्रतिदिन, दर्री बड़ी प्रतिदिन, पाईप पंडाल प्रति वर्ग फिट, वेलवेट कारपेट प्रति वर्ग फिट, टी टेबल प्रति नग, लक्कर स्टैण्ड प्रति नग, स्टेज निर्माण प्रति वर्ग फिट, पर्दा प्रति वर्ग फिट, गद्दा रुई प्रति नग, गद्दा डनलप प्रति नग, जनरेटर (तेल सहित) 7.5 के.व्ही. प्रति नग या प्रतिदिन, जनरेटर (तेल सहित) 15 के.व्ही. प्रति नग/प्रतिदिन, जनरेटर (तेल सहित) 30 के.व्ही. प्रति नग/प्रतिदिन, पंखा प्रति दिन/प्रति नग, कूलर प्रति दिन/प्रति नग, ए.सी. प्रति दिन/प्रति नग, ग्रीन मेट 15ग30 प्रति दिन/प्रति नग, फर्नीचर फोल्डिंग टेबल प्रति नग प्रति दिन/प्रति नग, कुर्सी प्रति नग (फाइबर) प्रति दिन/प्रति नग, सोफा प्रति सेट प्रति दिन/प्रति नग, सोफा (महाराजा) प्रति सेट प्रति दिन/प्रति नग। स्टेशनरी सामग्री, कम्प्यूटर टाईप लेटर टाईप प्रति पेज, एक्सेल टाईप प्रति पेज, ए-4 फोटो कॉपी प्रति पेज, एस.एफ. फोटो कॉपी प्रति पेज, ए-3 फोटो कॉपी प्रति पेज, स्पाईरल बाईडिंग 50 पन्ना तक, स्पाईरल बाईडिंग 50 पन्ना से उपर, स्टीकर (छोटा) प्रति नग, स्टीकर (बड़ा) प्रति नग। अन्य प्रचार सामग्री सायकिल रिक्शा (रैली/प्रचार) प्रति दिन, ढोल/नगाड़ा/मांदर प्रति घण्टा, बैण्डबाजा प्रति दिन, गमछा (छोटा) पार्टी चिन्ह सहित प्रति नग, गमछा (बड़ा) पार्टी चिन्ह सहित प्रति नग। विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए भोजन व्यवस्था की सूची लंच पैकेट दो सब्जी, अचार, सलाद, चावल दाल व 4 पूड़ी 1 पानी पाउच, स्वल्पाहार, 1 मीठा, 2 नमकीन एवं चाय, बिसलरी बॉटल पानी प्रति बॉटल/पाउच, चाय प्रति कप, कॉफी प्रति कप,विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की सूची वीडियोग्राफी सामग्री सहित संपूर्ण जिले में फोटोग्राफी संपूर्ण जिले में, वीडियो कैसेट प्रति सी.डी.,विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए प्रयोग किये जाने वाले सीलों की सूची एक लाईन सील प्रति नग, दो लाईन सील प्रति नग, तीन लाईन सील प्रति नग, चार लाईन सील प्रति नग, गोल सील 1 से.मी. से.मी. प्रति नग, चौकोर सील 1 से.मी. से.मी. प्रति नग, विधानसभा चुनाव 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 में चुनाव सामग्री एवं अन्य सामग्री की सूची चुनाव प्रसार सामग्री का विवरण कपड़े का बैनर लिखाई सहित प्रति वर्ग फुट झण्डा लिखाई सहित प्रति वर्ग फुट कपड़े का 1218 प्रति वर्ग फुट 12×30 प्रति वर्ग फुट, 12×36 प्रति वर्ग फुट, पोस्टर फुल साईज कलर 20×30 प्रति हजार, फुल साईज कलर 12×18 प्रति हजार, पोस्टर ए-4 साईज कलर में प्रति नग, सादा पेपर में प्रति नग, होर्डिंग्स/फ्लैक्सी फ्लैक्सीप्रति वर्ग फीट, वॉल पेंटिंग प्रति वर्ग फीट, नारा लेखन प्रति वर्ग फीट, कटआउट (कपड़ा/प्लास्टिक फिक्स करने सहित) प्रति वर्ग फीट, गेट निर्माण (स्वागत द्वार/बांस कपड़ा बैनर सहित) प्रति दिन, गेट निर्माण आर्च (स्वागत द्वार/बांस कपड़ा बैनर सहित) प्रति दिन, कलाजत्था प्रति कार्यक्रम नगर पालिका क्षेत्र में होर्डिंग्स किराया, शासकीय भूमि प्रति वर्ग फीट, निजी भेमि/भवन मालिक/नगरपालिका में पंजीकृत प्रति वर्ग फीट, स्वागत सामग्री गेंदा माला प्रति नग, महामाला प्रति फीट, बुके प्रति नग, गुलदस्ता प्रति नग, रींग प्रति नग, स्टेज डेकोरेशन (बाम्बे फेस्टिंग) प्रति फीट, ठहरने की व्यवस्था, सिंगल नॉन अटैच रुम प्रति दिन, डबल नॉन अटैच रुम प्रति दिन, सिंगल अटैच रुम प्रति दिन,सिंगल अटैच डीलक्स रुम प्रति दिन, डबल अटैच रुम ए.सी. प्रतिदिन, डबल अटैच डीलक्स रुम ए.सी. प्रति दिन।

पंजाब वक्फ बोर्ड ने खन्ना सर्कल में मस्जिदों की डेवलपमेंट के लिए 26.75 लाख की ग्रांट जारी की- एमएफ फारुकी

सत पाल सोनी
क्यूँ न लिखूँ सच

लुधियाना- खन्ना -पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से खन्ना सर्कल में भी मस्जिदों के विकास कार्यों के लेकर फंड जारी किया जा रहा है। पिछले पांच महीनों में पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से खन्ना सर्कल मे करीब 27 लाख रुपए का डेवलपमेंट फंड जारी किया गया है और कब्रिस्तानों को रिजर्व करने के साथ-साथ नई मस्जिदें जिन्हें 6-6 हजार रुपए महीना सहायता राशि भी जारी की जा रही है। एस्टेट अफसर मोहम्मद लियाकत ने बताया कि पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से एडमनिस्ट्रेटर एमएफ फारुकी की अगुआई में लगातातर बेहतर कार्य किया जा रहा है। खन्ना सर्कल में दर्जनों मस्जिदों की डेवलपमेंट के लिए 26 लाख

से ज्यादा का फंड जारी किया गया है जिसके तहत मदीना मस्जिद आजाद नगर खन्ना को 5 लाख, जामा मस्जिद समराला को 7.50 लाख, घुराला मस्जिद को 1 लाख रुपए, कामर्स मस्जिद को 50 हजार, मक्का मदीना मस्जिद को 1.50 लाख, मदीना मस्जिद को 1 लाख, मदीना मस्जिद गांव जर्ग को 1 लाख, नूरानी मस्जिद को 2 लाख, मदीना मस्जिद किला रोड़ को 2 लाख, मदीना मस्जिद को 1.50 लाख, मोहम्मदी मस्जिद 1.50 लाख, नुरानी जामा मस्जिद को 1 लाख, जामा मस्जिद खमाणो को 1.50 लाख रुपए की डेवलपमेंट ग्रांट जारी की गई है। इसके अलावा खन्ना सर्कल के तहत आती उस्मानिया मस्जिद और मोहम्मदी मस्जिद को 6-6 हजार रुपए महीना की आर्थिक मदद भी शुरू की गई है। एस्टेट अफसर मोहम्मद लियाकत ने बताया कि एडमनिस्ट्रेटर एमएफ फारुकी की अगुआई में लगातार मस्जिदों और मदरसों सहित कब्रिस्तान के विकास कार्यों को लेकर ग्रांट जारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों पर कानूनी कारवाई भी होगी और जो भी अवैध तरीके से पंजाब वक्फ बोर्ड की जगह पर काबिज है वह कानूनी तरीके से उसकी लीज जरूर करवाए। वहीं एमएफ फारुकी ने बताया कि पंजाब वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सूबे में कब्रिस्तानों को रिजर्व करना, मस्जिदों की डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम सहित हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को कानूनी तरीके से खाली करवाया जा रहा है।

फुड सेफ्टी आन की वैन के द्वारा व्यापारियों का जागरूकता अभियान

अरविन्द कुमार
क्यूँ न लिखूँ सच

श्रावस्ती - सिचाई विभाग द्वारा कटान को रोकने के लिए पत्थर लगाये गये जो मानक विहीन होने के कारण राप्ती नदी में होरहा समाहित श्रावस्ती राप्ती बैराज से लक्ष्मन पुर कोठी गाँव को राप्ती नदी के कटान को रोकने के लिए सिचाई विभाग द्वारा पत्थर लगाया गया है ,जो मानक विहीन होने के करण व कम उचाई होने के कारण राप्ती नदी का हल्का जल स्तर बढ़ने के कारण लगाया गया पत्थर धीरे धीरे राप्ती नदी में समायोजित हो रहा है , इस सम्बंध में गाँव के भोला प्रसाद पासवान , राम विलास , लहरी बाबू, पृथ्वी राज, रक्षा राम यादव, व अन्य ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेज कर जिलाधिकारी श्रावस्ती व मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश साशन , सिचाई मंत्री उत्तरप्रदेश लखनऊ को प्रार्थना पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग किया है

टमाटर, धनिया ने लगाया शतक, अदरक 300 पार, सब्जी हुई रसोई से बाहर

राम कुमार यादव
क्यूँ न लिखूँ सच

बस्ती- सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। महंगी हुई सब्जियों ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। इससे स्वाद भी गड़बड़ा गया है। 20 से 30 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर इतना लाल हुआ कि शतक पार हो गया और अब टमाटर आम लोगों की पहुंच से दूर रहा है। वहीं अदरक भी अपना रंग दिखा रहा है। बारिश, भीषण गर्मी और उमस का असर सीधे किचन पर पड़ा है। आम आदमी की भोजन की थाली मंहगाई की मार से कमजोर पड़ती जा रही है। खाने की थाली से टमाटर, अदरक, लहसुन और नींबू भी दूर होने लगा है। हालत यह है कि मौसम की मार में उपज प्रभावित होने और बिचौलिए की कमाई में टमाटर, लहसुन और अदरक थोक मंडी में सैकड़ा पार कर गई है। जबकि लौकी, कद्दू, परवल, धनिया, मिर्च आदि के दाम भी आसमान छू रहे हैं। मंडी से जो सब्जियां आ रही हैं, वह फुटकर बाजार में आते-आते कई गुना दाम बढ़ जा रहे हैं। इससे लोगों को समस्या हो रही है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मनाया अपना 75वा स्थापना दिवस

सत पाल सोनी
क्यूँ न लिखूँ सच

लुधियाना- पेशेवर उत्कृष्टता की गौरवशाली परंपरा का पालन करते हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई, 2023 को अपने शानदार अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और ऐतिहासिक अवसर है, जो देशवासियों को अकाउंटेंसी पेशे की अद्भुत चल रही यात्रा की याद दिलाता है। सफलता की शुरुआत दशकों पहले 1 जुलाई, 1949 को आईसीएआई की स्थापना के साथ हुई थी। यह न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम की शुरुआत टीम लुधियाना शाखा द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुई। आईसीएआई की उत्कृष्टता की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी

प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए इस अवसर पर बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए छात्र उपस्थित थे। शाखा अध्यक्ष सीए वासु अग्रवाल ने इस शुभ अवसर पर पेशे से जुड़े सभी सदस्यों और सीए छात्रों को बधाई दी। उन्होंने अपने सदस्यों और सीए छात्रों के लिए लुधियाना शाखा की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया और कहा कि यह आयोजन सदस्यों और उनके परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को और बढ़ावा देगा। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने भरपूर सहयोग किया। इस नेक कार्य के लिए लगभग 90 यूनिट रक्तदान किया गया। सीए को स्वास्थ्य की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से, श्री कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क शुगर, बीपी, चिकित्सा परामर्श का आयोजन किया गया, डॉ. ऋषि अग्रवाल, अग्रवाल डेंटल क्लिनिक एवं इम्प्लांट सेंटर, द्वारा दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण स्वतंत्र रूप से किए गए और लगभग 100 सदस्य लाभान्वित हुए।इस मौके पर लुधियाना आईसीएआई ब्रांच के चेयरमैन सीए वासु अग्रवाल, वाइस चेयरमैन सीए. मोहित वासन, सचिव सीए सुबाष बंसल, कोषाध्यक्ष सीए राकेश ग्रोवर, निकासा सदस्य सीए. अवनीत सिंह, वरिष्ठ सदस्य, सीए। रोमेश कुमार अग्रवाल, सीए अमरजीत कंबोज, सीए बाल महाजन, सी.ए. विशार्ल एनआईआरसी पूर्व अध्यक्ष, सीए जसमिंदर सिंह पूर्व अध्यक्ष, इस मौके पर पूर्व चेयरमैन सीए संदीप गुप्ता भी मौजूद रहे।

फुड सेफ्टी आन की वैन के द्वारा व्यापारियों का जागरूकता अभियान

प्रेमचंद जायसवाल
क्यूँ न लिखूँ सच

श्रावस्ती जमुनहा मे फूड सेफ्टी आन (एफएसडब्ल्यू) की वैन के द्वारा व्यापारियों मे जागरूक करने के लिए गाड़ी के साथ बाजारों मे जाकर जागरूकता की जा रही है। कुछ व्यापारियों मे जागरूकता के आभाव से व्यापरियो मे दहशत हुई जो

अपनी दुकान की शटर गिराकर गयाब हुए। वही किसी तरह व्यापारियों को समझा बुझाकर जागरूकता की गयी। जमुनहा बाजार, वीरगंज बाजार मे फूड सेफ्टी आन स्वस्छ्ता के माध्यम से व्यापारियों को मौके पर ही खाद्य प्रदार्थो की जाँच करके उसमे पायी गयी कमियों को बताया गया।तथा उसमे सुधार के निर्देश दिये गये एवं स्वस्थ्य पर्द, खाद्य प्रदार्थो को का विक्रय करने हेतु निर्देश देते हुए जागरूक किया गया है। एफएसडब्ल्यू के टीम के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्र यादव इकौना, अजय कुमार श्रीवास्तव जमुनहा द्वारा व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए व्यापारियों को दिखाते खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्र यादव इकौना।

राज्यमंत्री डॉ अरुण कुमार ने किया शुभारंभ, 31 जुलाई तक चलेगा यह विशेष अभियान

सत्यम शर्मा
क्यूँ न लिखूँ सच

बरेली- डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए अगले एक महीने तक चलने वाला संचारी रोग अभियान शनिवार को शुरू हुआ। वन पर्यावरण राज्यमंत्री डॉ अरुण कुमार ने सीबीगंज यूपीएचसी पर फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया। अर्बन नोडल अधिकारी डॉ सीपी सिंह, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ प्रशांत रंजन और सीबीगंज यूपीएचसी की प्रभारी डॉ. मधु गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली का आगाज किया एवं संचारी रोग नियंत्रण करने के लिए सभी को शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्यमंत्री ने कहा कि बारिश में जलभराव से मच्छर पनपते हैं और इससे डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए संचारी रोगों से बचने के लिए आसपास की सफाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को टीबी और फाइलेरिया से बचाव की भी जानकारी दें। लोग बीमारियों के बारे में जागरूक रहेंगे तो उससे बचाव करना भी आसान होगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ.प्रशांत रंजन ने बताया कि मच्छरों से डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलता है। बचाव के लिए नालियों की सफाई व झाड़ियों की कटाई जरूरी है। जिन हैंडपंप में पीला निशान लगाया जाता है, पीने के पानी का उपयोग इसी हैंडपंप से करना चाहिए। इसके अलावा पानी को उबालकर ठंडा कर पीना बेहतर उपाय है। उन्होंने बताया कि बच्चों को जापानी बुखार से बचाने के लिए नौ माह और 16 माह पूर्ण होने पर जेई टीका जरूर लगवाना चाहिए। इस अवसर पर मण्डलीय सर्विलांस अधिकारी डॉ अखिलेश्वर सिंह, डब्ल्यूएचओ से डॉ. कौशिक, चाई से फैज़ान अली और मनीष, जेएसआई से शमीम, डीएमओ डीआर सिंह, और यूएनडीपी से धर्मेंद्र चौहान, फैमिली हेल्थ इंडिया से दुर्गेश अग्रवाल, डब्ल्यूएचओ से फील्ड मॉनिटर नरेंद्र कुमार उपस्थित रहे।

जनमानस भी हो रहा जागरूक

सीबीगंज निवासी रोहिताश ने बताया कि बरसात के दिनों में उनके घर के आसपास बहुत मच्छर हो जाते हैं जिससे बचने के लिए वह नालियों की सफाई कराते हैं। अगर किसी को बुखार हो जाए तो वह फौरन अस्पताल में दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि सही इलाज मिल सके। बिधौलिया निवासी शाहीन ने बताया कि वह मच्छरदानी का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा घर के आसपास और मोहल्ले में भी सफाई का ध्यान रखती हैं।

अभिभावक व छात्रों का भी करेंगे संवेदीकरण

डीएमओ डीआर सिंह ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से दिमागी बुखार व अन्य वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जेई/एईएस, कालाजार, स्क्रबटाइ?फस, लेप्टोस्पाइरोसिस और जलजनित रोगों, लू आदि से बचाव, रोकथाम व उपचार के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तकों के वितरण के समय अभिभावकों का भी संवेदीकरण किया जाएगा। स्कूलों में पोस्टर प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतिस्पर्धा, निबंध लेखन आदि के माध्यम से छात्रों को रोगों से बचाव, पर्यावरणीय स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में बताया जाएगा।

17 जुलाई से शुरू होगा दस्तक अभियान

संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान ही 17 जुलाई से दस्तक अभियान शुरू होगा। इस दौरान घर-घर संपर्क कर रहीं आशा स्टीकर लगाकर सुनिश्चित करेंगी कि घर के सदस्य किसी भी तरह के बुखार के समय नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर संपर्क करें।

अभियान के दौरान आशा रोज अपने काम की सूचना एएनएम को उपलब्ध कराएंगी। आशा बुखार, इन्फ्लुएंजा ग्रसित लोगों, क्षय रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों, कुपोषित बच्चों और ऐसे मकान जहां घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन पाया गया हो, उनकी जानकारी मुहैया कराएंगी। यह बातें रखें ध्यान- डेंगू, चिकनगुनिया का एडीस मच्छर दिन में काटता है एवं कृत्रिम रूप से इकट्ठा हुए पानी में पनपता है जापानी बुखार एवं फाइलेरिया फैलाने वाला क्यूलेक्स मच्छर रात में काटते हैं और रुके हुए पानी में पनपते हैं मलेरिया फैलाने वाला एनाफिलीज मच्छर शाम से सुबह तक काटता है एवं साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है

राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की बैठक में व्यापारियों ने आ रही कठिनाइयों को हल का समर्थन का आश्वासन दिया-सुनील मेहरा

सत पाल सोनी
क्यूँ न लिखूँ सच

लुधियाना- भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अति आवश्यक बैठक नई दिल्ली में राष्ट्रीय चेयरमैन बाबू लाल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में ऑनलाइन इनकम टैक्स , जी एस टी और व्यापार में आ रही कठिनाइयों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और फैसला किया गया है कि 9 अगस्त को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा । व्यापारियों की समस्याओं का विस्तृत चार्ट पेश कर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएंगे । आज की बैठक में विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई व्यापारी कल्याण बोर्ड का स्वागत किया गया । उसमें भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के दो अखिल भारतीय उप प्रधान सुनील मेहरा भी लिये गये। जिसका सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने दोशाला डाल कर स्वागत किया । इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड में लिये गये सदस्य सुनील मेहरा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड बनाकर अपना वायदा पूरा किया है और जो भी व्यापारियों को समस्याएं देश भर में आ रही हैं जिसमें विशेष तौर पर पंजाब में जहां व्यापार अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और उसके लिए केंद्र सरकार के सभी विभाग पंजाब के व्यापार और देश भर के व्यापार उद्योग को समर्थन देने के लिए विशेष बातचीत की जाएगी और उसके लिये सभी व्यापारियों के सुझाव और विचार लेकर होने वाली व्यापार कल्याण बोर्ड की मीटिंग में सरकार के समक्ष रखी जाएगी और स्माल इंडस्ट्रीज स्माल ट्रेड के हित में जो भी कार्रवाई और फैसले किये जाएंगे । उन्होंने कहा कि स्मॉल इंडस्ट्री और सभी व्यापारियो की आवाज बन कर केंद्र सरकार से सभी व्यापारियों की समस्याऐ जैसे कि जी एस टी , इनकम टैक्स और भी कई समस्याएं को हल किया जाएगा और जो भी कठिनाईया व्यापारियों को आ रही है उसे दूर किया जाएगा। यह व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए बना है और व्यापारियों को आ रही सभी समस्याओं को हल करने के लिए अनथक पर्यतन किए जाएंगे।

सुपर जोइनिंग वीक
उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड,छत्तीसगढ़ पंजाब का तेजी से बढ़ता आपका अपना
दैनिक क्यूँ न लिखूँ सच & KNLS Live
आवश्यकता है भारत के सभी राज्यों से
रिपोर्टर,विज्ञापन प्रतिनिधि की
12 पेज का फुल अखबार
एक बार कॉल अवश्य करे
9027776991
प्रसारित क्षेत्र - उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड,छत्तीसगढ़ पंजाब बाकि राज्यों से जल्द प्रसारित

दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट

श्याम जी कश्यप
क्यूँ न लिखूँ सच

फर्रुखाबाद-दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट 2 दिन पूर्व दबंग घर में घुसकर ही बच्चे कर चुके हैं छेड़छाड़ रोहित ने दबंगों के खिलाफ थाने में दी तहरीरकस्बा इंचार्ज ने नहीं की थी दबंगों के खिलाफ कार्रवाईपीठ ने कस्बा इंचार्ज पर में भगत का लगाया आरोपथाना कमालगंज क्षेत्र के माहेरू पुर रवि का मामला

पुराने विवाद में दबंगों ने जमकर की मारपीट

श्याम जी कश्यप
क्यूँ न लिखूँ सच

फर्रुखाबाद- कायमगंज पुराने विवाद में दबंगों ने जमकर की मारपीट दबंगों ने लाठी-डंडे ईट पत्थर से किया हमला दबंगों की मारपीट में 3 लोगों के आयी गंभीर चोट है शोरगुल सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे मारपीट कर रहे दबंग छोड़कर मौके से फरार घायल अवस्था में तीनों को सीएससी कायमगंज में कराया गया भर्ती कायमगंज कोतवाली के आ ताही पुर जाजीद का मामला

जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान ने मत्स्य पालन,पशुपालन और डेयरी केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का लुधियाना पहुंचने पर किया स्वागत

सत पाल सोनी
क्यूँ न लिखूँ सच

लुधियाना- लुधियाना के गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय केंद्रीय में विशेष अतिथि के रूप में आऐ हुए मत्स्य पालन,पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान व उनके साथ जिला महामंत्री सरदार नरेंद्र सिंह मल्ही,जिला उपाध्यक्ष मनीष चोपड़ा लकी ने लुधियाना पहुंचने पर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान ने कहा कि पशुधन आजीविका कमाने काएक महत्वपूर्ण रूप ग्रहण करता है, यह आय में वृद्धि करता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है। भाजपा जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान ने कहा की पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। डेयरी सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है

काफी नकदी सहित दो सटोरिया भाइयों को गिरफ्तार

हारून बख्श
क्यूँ न लिखूँ सच

फर्रुखाबाद आदर्श थाना मऊ दरवाजा पुलिस ने काफी नकदी सहित दो सटोरिया भाइयों को गिरफ्तार किया है थाना पुलिस ने सटोरियों को पुलिस लाइन के सभागार में मीडिया के सामने पेश किया पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने मीडिया को बताया कि मऊदरवाजा थानाध्यक्ष आमोद कुमार ने इंस्पेक्टर अमित गंगवार व एसओजी टीम के साथ मकान में सट्टे की खाई वाली करने वालों की तलाश में बीती रात छापा मारा

पुलिस ने मोहल्ला हाता रोशन खान निवासी सुरेश वर्मा के पुत्र आकाश वर्मा व सनी वर्मा को घर में सट्टे की खाई बारी करते गिरफ्तार किया पुलिस ने मौके से 1.82.050 सट्टा पर्ची लैपटॉप 5 मोबाइल फोन आदि बरामद की है चर्चा है कि थाना पुलिस ने नए एसपी विकास कुमार को खुश करने के लिए सटोरियों के पास से काफी धनराशि की बरामदगी दर्शाई है पुलिस ने दोनों भाइयों के के सभी परिजनों की नगदी जप्त कर ली। सभी रुपए सट्टे की खाई बाड़ी में दर्शाए गए हैं बताया जाता है कि थाना मऊदरवाजा पुलिस ने आज तक किसी सटोरिए के पास से इतनी बड़ी नकदी बरामद नहीं की है कई वर्षों से इन सटोरियों की गिरफ्तारी नहीं की गई थाना मऊदरवाजा के सामने रहने वाला छोटू उर्फ इरफान पुलिसिया संरक्षण के कारण बीते कई वर्षों से खुलेआम सट्टा करता है बाईपास के निकट चर्चित महिला बीते कई वर्षों से काफी बड़े पैमाने पर सट्टा का धंधा करती है काफी प्रयास करने के बावजूद पुलिस इस महिला को कभी गिरफ्तार किया जबकि महिला को पकड़ने के लिए काफी पुलिस फोर्स के साथ छापे मारे गए। पुलिस अधीक्षक के कड़े रुक को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल सट्टे की कमाई से तौबा कर लेना महसूस किया जा रहा है

जान ले रहे गंगा एक्सप्रेस-वे पर बने गड्ढे डूबने से दो किशोरों की मौत, चीखती रही बहन; मदद को नहीं आए कर्मचारी

बदायूं के बिसौली तहसील क्षेत्र के गांव ऐपुरा में शनिवार सुबह गंगा एक्सप्रेस-वे के गड्ढे में डूबकर दो किशोरों की मौत हो गई। 13 वर्षीय फुरकान पुत्र तसव्वर और 14 वर्षीय आमीन पुत्र सफी मोहम्मद अपनी बहन फूलवानो के साथ खेत में धान की रोपाई करने गए थे। उधर से लौटते समय दोनों किशोर गंगा एक्सप्रेस-वे के गड्ढे में अपने पैर धो रहे थे। तभी अचानक दोनों फिसल गए और उनकी गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। डीएम मनोज कुमार ने बताया कि हमने इस मामले में तीन दिन पहले ही निर्देश दिए थे कि गंगा एक्सप्रेस-वे के अधिकारी जहां-जहां गड्ढे किए हैं, वहां बैरिकेडिंग कराएं। हादसा शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। फुरकान के पिता तसव्वर के मुताबिक फुरकान, आमीन और उसकी बहन फूलवानो ने गांव के एक व्यक्ति के खेत में धान रोपाई का ठेका लिया था। इससे दोनों किशोर, फूलवानो व मोहल्ले के कुछ और बच्चे गांव से करीब डेढ़ किलो मीटर दूर गंगा एक्सप्रेस-वे के नजदीक खेत में धान की रोपाई करने गए थे।बताते हैं कि उन्होंने कुछ खेत में धान की रोपाई भी की लेकिन खेत में पानी कम था। इससे सभी बच्चे घर लौट रहे थे। उन्होंने खेत मालिक से बोल दिया था कि वह जब खेत में पानी कर ले, तभी वह खेत पर आकर रोपाई शुरू कर देंगे। फुरकान, आमीन और फूलवानो एक साथ में थे।

20 फुट गहरा है गड्ढा

नजदीक में गंगा एक्सप्रेस-वे के नीचे पानी निकास को एक अंडरपास बनाया जा रहा है। उस अंडरपास के आगे करीब 15-20 फुट गहरा गड्ढा है। लगातार बरसात होने से उसमें पानी भर गया था। घर आने के दौरान फुरकान और आमीन उसी गड्ढे में अपने पैर धो रहे थे, तभी अचानक दोनों बच्चे उस गड्ढे में गिर गए। पास में खड़ी फूलवानो ने नजदीक में काम कर रहे गंगा एक्सप्रेस-वे के कर्मचारियों को बुलाने के लिए आवाज लगाई गई लेकिन उन्होंने आठ साल की बालिका की एक नहीं सुनी। फूलवानो दौड़ती हुई अपने गांव पहुंची और शोर मचाते हुए उसने लोगों को जानकारी दी। कुछ ही देर में तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। उससे पहले दो राहगीरों ने फुरकान को बाहर निकाल लिया। उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब दो घंटे बाद आमीन को निकाला गया। तब तक उसकी भी मौत हो गई। इसकी सूचना पर एसडीएम विजय कुमार मिश्र, सीओ बिसौली पवन कुमार और थाना पुलिस पहुंच गई। दोनों किशोरों के शव पोस्टमार्टम को भेजे गए हैं। डीएम बोले- जांच कराएंगे डीएम मनोज कुमार ने बताया कि हमने इस मामले में तीन दिन पहले ही निर्देश दिए थे कि गंगा एक्सप्रेस-वे के अधिकारी जहां-जहां गड्ढे किए हैं, वहां बैरिकेडिंग कराएं। आज जहां घटना हुई है, वहां बैरिकेडिंग नहीं थी। की जांच कराएंगे। इसमें जो भी दोषी होगा। उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक आरएन त्रिपाठी ने बताया कि इस समय गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण चल रहा है। हम अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं कि जब तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो, तब तक उसके नजदीक गांव का कोई व्यक्ति या बच्चा नहीं आए। हमने लोगों को भी जागरुक किया था। इसके बावजूद बच्चे पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चों के माता-पिता जिम्मेदार हैं।

2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से रेलवे ट्रैक पर भरा पानी

श्याम जी कश्यप
क्यूँ न लिखूँ सच

फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से रेलवे ट्रैक पर भरा पानी रेलवे ट्रैक पर पानी भरा होने से हो सकता है बड़ा हादसा रेलवे ट्रैक पर लबालब पानी भरा होने से मिट्टी धंसने क भय रेलवे के तरफ से पानी निकालने के नहीं किए गए कोई इंतजाम फर्रुखाबाद फतेहगढ़ नेपुर पुल के बीच रेलवे ट्रैक का मामला

उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका, अब बेटे आदित्य के करीबी राहुल कनाल ने थामा शिंदे गुट का दामन

राहुल कनाल को आदित्य ठाकरे के बेहद करिबियों में गिना जाता है। वह युवा सेना के सक्रिय सदस्य थे। वह, युवा सेना की कोर कमेटी में भी थे। हालांकि इसकी कार्यप्रणाली से परेशान होकर उन्होंने कोर कमेटी से दूरी बना ली थी। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद से उद्धव गुट को एक के बाद एक झटके लगातार लग रहे हैं। अब पूर्व सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे के एक करीबी राहुल कनाल ने उद्धव गुट का साथ छोड़ दिया है।

अब वे सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं।इससे पहले उन्होंने खुद कहा था कि वे और उनके साथ खई अन्य कार्यकर्ता भी शनिवार दोपहर के शिवसेना में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि उद्धव ठाकरे कुछ लोगों के कहने पर और उनकी सलाह से अपनी पार्टी में फैसले लेते हैं। स्वाभिमान नाम की भी कोई चीज होती है। गौरतलब है कि राहुल कनाल उस दिन शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिस दिन आदित्य ठाकरे ने मुंबई नागरिक निकाय बृहन्मुंबई नगर निगम या बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व किया। हुल कनाल को आदित्य ठाकरे के बेहद करिबियों में गिना जाता है। वह युवा सेना के सक्रिय सदस्य थे। वह, युवा सेना की कोर कमेटी में भी थे हालांकि इसकी कार्यप्रणाली से परेशान होकर उन्होंने कोर कमेटी से दूरी बना ली थी। इससे पहले, राहुल कनाल को शिरडी में साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट -श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट (एसएसएसटी) के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 2017 में बीएमसी की शिक्षा समिति के सदस्य भी थे। बता दें कि राहुल कनाल से पहले, इस महीने की शुरुआत में एमएलसी मनीषा कायंदे ने भी ठाकरे गुट छोड़ दिया था। शिंदे की टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी मामलों पर प्रतिक्रिया के लिए उद्धव ठाकरे उपलब्ध नहीं रहते हैं। वहीं, उनके शिंदे गुट में शामिल होने से एक दिन पहले वरिष्ठ नेता शिशिर शिंदे ने भी उद्धव का साथ छोड़ दिया था।

बेसहारा हुईं तीन बेटियां: पति की हत्या कर पत्नी गई जेल, बेटी बोली- मम्मी कहती थी पापा को रास्ते से हटा देंगे

मेरठ में खरखौदा क्षेत्र के फफूंडा के 40 वर्षीय धर्मवीर की हत्या के मामले में उसकी पत्नी संतलेश की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का राजफाश हो गया। एसपी देहात कमलेश बहादुर ने बताया कि संतलेश के प्रेमी जाहिदपुर गांव निवासी सौरभ ने पहले नशीली गोलियां मिलाकर शराब पिलाई थी। इसके बाद पत्नी ने धर्मवीर को नदी में धक्का दे दिया था। पति की हत्या के मामले में पत्नी जेल चली गई। अब उनकी तीन बेटियां बेसहारा हो गईं। मासूम बेटी कृतिका ने बताया कि मम्मी कहती थी पापा को रास्ते से हटा देंगे।एसपी देहात के मुताबिक किताबों की फैक्टरी में काम करने के दौरान सौरभ और संतलेश में संबंध हो गए थे। कुछ समय पहले धर्मवीर ने अपनी जमीन बेची थी, जिसके पांच लाख रुपये संतलेश के खाते में जमा कराए गए थे। संतलेश ने थोड़ी-थोड़ी रकम अपने प्रेमी सौरभ को भेज दी थी। धर्मवीर को इसका पता चला कि उसने संतलेश के साथ मारपीट कर दी थी। इस बीच धर्मवीर बीमार भी चल रहा था। छानबीन में पता चला कि 26 जून को संतलेश उसे उपचार के लिए शाहदरा लेकर गई। वहां से 27 जून को उसे वापस लेकर खरखौदा पहुंची। खरखौदा बाईपास पर संतलेश का प्रेमी सौरभ और उसके दो साथी मिले। सौरभ ने नशे की गोलियां मिलाकर शराब धर्मवीर को दे दी। इससे धर्मवीर को अधिक नशा हो गया था। इसके बाद संतलेश समेत चारों आरोपी बाइक पर धर्मवीर को बैठाकर असरा की ओर जाने वाले रास्ते पर काली नदी के पुल पर पहुंचे। यहां धर्मवीर को नशे की हालत में बाइक से उतारा और संतलेश ने उसे काली नदी में धक्का दे दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पानी में डूबने के कारण मौत की पुष्टि हुई है।

पत्नी ने कराई घटनास्थल की निशानदेही

धर्मवीर की पत्नी संतलेश की गिरफ्तारी के बाद खरखौदा थाना पुलिस उसे लेकर काली नदी के पुल पर भी पहुंची। वहां पर घटनास्थल की निशानदेही कराई गई। इसमें संतलेश ने बताया कि उसने धर्मवीर को कैसे धक्का दिया था। संतलेश को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है, जबकि प्रेमी और उसके दो साथी फरार हैं।

पिता की हत्या, मां जेल में, बेसहारा हुई तीन बेटियां

धर्मवीर के परिवार में उसकी तीन बेटियां हैं। बड़ी बेटी 10 वर्षीय कृतिका, दूसरी नौ वर्षीय अंशु और तीसरी चार वर्षीय मुनमुन है। धर्मवीर तीनों बेटियों व पत्नी के साथ अपने छह भाइयों से अलग रहता था। धर्मवीर की हत्या के बाद बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया है। मां के जेल जाने के बाद उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं है। हालांकि परिवार के लोग उन्हें दिलासा दे रहे हैं।

मम्मी कहती थी पापा को रास्ते से हटा देंगे - कृतिका

इस प्रकरण के बाद बड़ी बेटी कृतिका अपनी मां को कोस रही है। वह बार-बार कह रही थी कि उसकी मम्मी हर समय फोन पर सौरभ से बात करती थी। वह कई बार कह चुकी थी कि पापा को रास्ते से हटाकर सभी आराम से रहेंगे। उसने कई बार मम्मी संतलेश और सौरभ को बातचीत करते हुए भी सुना था।

यह था मामला

फफूंडा निवासी धर्मवीर का शव बुधवार को हापुड़ में मिला था। शक के आधार पर बृहस्पतिवार को उसकी पत्नी संतलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिसने बताया कि उसने प्रेमी सौरभ और दो अन्य के साथ मिलकर धर्मवीर की हत्या की है।

पुलिस की गिरफ्त में चंद्रशेखर पर हमला करने वाले चार आरोपी, अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने की थी तैयारी

चंद्रशेखर पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों को हरियाणा के अंबाला से पकड़ा है। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हमला करने वाले चार आरोपियों को सहारनपुर पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से पकड़ा है। बताया गया ये चारों आरोपी अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे। बताया गया कि ये चारों आरोपी पुलिस से साठगांठ कर कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे। इसी दौरान थाना पुलिस की इन पर नजर पड़ गई। इसके बाद उन्हें दबोच लिया गया है। वहीं, सहारनपुर पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी।

यह था मामला

बुधवार की शाम देवबंद की गांधी कॉलोनी से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर कार में अपने भाई मनीष और तीन अन्य साथियों के साथ सहारनपुर लौट रहे थे। यूनियन तिराहे के पास स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने चंद्रशेखर की कार पर चार राउंड फायरिंग की। एक गोली कार के दरवाजे को भेदते हुए चंद्रशेखर के पेट को छूकर निकल गई, जिससे वह घायल हो गए। देवबंद सीएचसी के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के आरोपी कार सहित मौके से फरार हो गए थे। बृहस्पतिवार शाम को चंद्रशेखर को जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

समृद्धि एक्सप्रेसवे दुर्घटना पर शरद पवार ने साधा निशाना, बोले- सड़क योजना बनाने वाले दोषी

समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि हादसों की अहम वजह सड़क का काम वैज्ञानिक तरीके से नहीं होना है समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शनिवार को भीषण बस हादसे में 25 यात्रियों की मौत हो गई। समृद्धि हाईवे पर हुआ यह सबसे बड़ा और भयानक हादसा था। एक निजी बस लोहे के खंभे से टकरा गई और उसमें आग लग गई। रात के दौरान बस में सोए हुए यात्री आग की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बस में यात्री नागपुर, यवतमाल, वर्धा जिले के थे। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोग समृद्धि एक्सप्रेसवे सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं देखते हैं, दुर्घटनाओं में मरने वाले लोग देवेंद्रवासी हो रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हादसों की अहम वजह सड़क का काम वैज्ञानिक तरीके से नहीं होना है, इसके लिए सड़क बनाने की योजना बनाने वाले दोषी हैं। पिछले कुछ वर्षों में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं और लगातार हो रही हैं।एनसीपी अध्यक्ष पवार ने कहा कि मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि समाधान नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। मार्ग पर साइनबोर्ड की कमी है जिसकी शिकायतें आती रहती हैं। पूरे मार्ग की गहन निरीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि इसे आवागमन के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। 701 किलोमीटर लंबा नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे विदर्भ के सबसे बड़े शहर नासिक के भारविर तक 601 किलोमीटर की दूरी पर चालू है और इसको फडणवीस की योजना माना जाता है। हालाँकि, पिछले साल 12 दिसंबर को इसे जनता के लिए खोले जाने के बाद से यहां कई बड़ी दुर्घटनाओं हुई हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के भाजपा का बीएमसी के खिलाफ आंदोलन स्थगित-समृद्धि एक्सप्रेसवे बस दुर्घटना में 25 लोगों की जान चली गई, इसको देखते हुए भाजपा ने शनिवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में अपना आक्रोश आंदोलन स्थगित कर दिया है। भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने ट्विटर पर एक्सप्रेसवे दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। शेलार ने ट्वीट करके कहा कि हमने 25 साल तक मुंबई को लूटने वालों के खिलाफ भाजपा के विरोध प्रदर्शन को रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि, हम उनसे सवाल पूछना जारी रखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता का मामला बड़ी बेंच को भेजा; हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका

गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर झूठे सबूत गढ़ने से जुड़े एक मामले में तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, चूंकि आवेदक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर है, इसलिए उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का प्रयास किया और उन्हें जेल भेजने की कोशिश की। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से सीतलवाड को आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए था। इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश पारित किया गया था। वह नौ महीने से जमानत पर हैं। हम सोमवार या मंगलवार को इस मामले पर विचार कर सकते हैं, 72 घंटों में क्या होने वाला है?

दोनों जजों का मत-अलग-अलग

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ में दोनों जज की राय अलग-अलग रही। ऐसे में पीठ ने मामले को बड़ी बेंच के सामने रखने के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया।

हाईकोर्ट ने दिया तत्काल आत्मसमर्पण का निर्देश

इससे पहले न्यायमूर्ति निर्जर देसाई की अदालत ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया क्योंकि वह अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद पहले ही जेल से बाहर हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा, चूंकि आवेदक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, इसलिए उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने आदेश की घोषणा के बाद सीतलवाड़ के वकील द्वारा मांगी गई 30 दिनों की अवधि के लिए आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा

अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सीतलवाड़ ने अपने करीबी सहयोगियों और दंगा पीड़ितों का इस्तेमाल सरकार को अस्थिर करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री (नरेंद्र मोदी) की छवि को खराब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष झूठे और मनगढ़ंत हलफनामे दाखिल करने के लिए किया। अदालत ने कहा कि यदि आज किसी राजनीतिक दल ने कथित तौर पर उन्हें (तत्कालीन) सरकार को अस्थिर करने का काम सौंपा है, तो कल कोई बाहरी ताकत इसका इस्तेमाल कर सकती है और किसी व्यक्ति को इसी तरह के प्रयास करने के लिए मना सकती है, जिससे देश या किसी विशेष राज्य को खतरा हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीतलवाड़ को जमानत पर रिहा करने से यह गलत संकेत जाएगा कि एक लोकतांत्रिक देश में सब कुछ इतना उदार है कि भले ही कोई व्यक्ति तत्कालीन सरकार को सत्ता से हटाने और तत्कालीन मुख्यमंत्री की छवि को बदनाम करने के प्रयास करने की हद तक चला जाए और उसका दोष माफ भी किया जा सकता है। अदालत ने कहा, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।

क्या है मामला?

बता दें कि सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ अहमदाबाद अपराध शाखा पुलिस द्वारा दर्ज अपराध में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में कथित तौर पर 卐निर्दोष लोगों卐 को फंसाने के लिए मनगढ़ंत सबूतों के इस्तेमाल करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने 30 जुलाई, 2022 को मामले में सीतलवाड़ और श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों को यह संदेश जाएगा कि कोई व्यक्ति बिना किसी दंड के आरोप लगा सकता है और बच सकता है। हाईकोर्ट ने तीन अगस्त, 2022 को सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले की सुनवाई 19 सितंबर को तय की थी। इस बीच, उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दो सितंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी और उनसे तब तक ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था, जब तक गुजरात हाईकोर्ट उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं कर देता। शीर्ष अदालत ने उनसे मामले की जांच में जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने को भी कहा था। सीतलवाड तीन सितंबर को जेल से बाहर आई थीं। जकिया जाफरी मामले में शीर्ष अदालत के 24 जून के फैसले के कुछ दिनों बाद सीतलवाड़ और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ध्या से लौट रहे हिंदू कारसेवक थे, जलकर मर गए थे। पिछले महीने ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोपमुक्त करने की पूर्व डीजीपी श्रीकुमार की याचिका भी खारिज कर दी थी। श्रीकुमार गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दिए गए मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। मामले के तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। जब भट्ट को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो वह पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में जेल में थे।

Why is terror spreading Pakistan afraid to send its team to India? Know the whole matter

The ODI World Cup is going to start in India from October 5. In such a situation, Pakistan is ready to send a security team to India to inspect the venues before approving the Babar Azam-led team. Now a new drama of Pakistan promoting terror has started. It has decided to send a security team to India to take stock of the security situation ahead of the World Cup. Earlier, the Pakistan Cricket Board (PCB) had talked about considering the decision of sending its cricket team to India for the World Cup. PCB had said that this decision rests with their government. Responding to this, the ICC had said that the PCB has entered into an agreement and now it cannot back down. ODI World starting from 5th October - The ODI World Cup is going to start in India from 5th October. In such a situation, Pakistan is ready to send a security team to India to inspect the venues before approving the Babar Azam-led team. An official source in the Inter-Provincial Coordination (Sports) Ministry told news agency PTI that holidays and the new PCB Pakistan will decide when to send the security delegation to India. However, it is not decided whether it will be approved by the Government of India or not. "The security delegation along with the representation will go to inspect the venues where Pakistan will play and also inspect the security and other arrangements made for them in the World Cup," the source said.

The source said the delegation would visit Chennai, Bengaluru, Hyderabad and Kolkata, including Ahmedabad, the venue of the India-Pakistan match on October 15.The security delegation will inspect these things, the official told PTI, "It is standard practice for the cricket board to take permission from the government before any tour of India, which usually sends a delegation to India. The delegation will interact with the officials there and hold discussions and inspections with them. Will also see to the security and other arrangements for our players, officials, fans and media going for the tournament. "He said that if the delegation felt that it would be better for Pakistan to play at any other venue than that venue, then He will mention it in his report. The venue of the India-Pakistan match was changed in 2016 as well - he said, "If the delegation has any concerns about any venue, the PCB will share the report with the ICC and the BCCI." A PCB source confirmed that the last time Pakistan traveled to India for the T20 World Cup, the government had sent a joint delegation to India to inspect the venues. It was on the recommendation of the delegation that Pakistan's match against India in Dharamsala was shifted to Kolkata. What is Pakistan's strategy behind sending the delegation to India?In fact, the ICC and the BCCI had turned down Pakistan's demand for a change in the venue of the two matches. These include Chennai, Bangalore and Ahmedabad. In such a situation, Pakistan is looking for a new way to change the venue by sending a team of experts.Pakistan is afraid to play Pakistan in front of Afghanistan spinners in Chennai, Australia's explosive batsmen in Bengaluru and one lakh 30 thousand spectators in Ahmedabad. In the 2016 T20 World Cup also, citing security reasons, the PCB changed the venue of the India-Pakistan match. Was changed. Then the match was shifted from Dharamshala to Eden Gardens in Kolkata. In such a situation, Pakistan is now making a new effort to change the venue. The ICC also looks into the matter carefully citing security reasons. The ICC doesn't even look at the demand for change of venue just because of the pitch. The ICC says that in such a situation any country will start demanding favours. Earlier, the ICC had announced the ODI World Cup schedule to be held in India on June 27. As per the schedule, Pakistan will lock horns with India on October 15 in Ahmedabad. At the same time, it will compete with Australia (October 20) at Chinnaswamy in Bengaluru and Afghanistan (October 23) at Chepauk, Chennai. Soon after this announcement, the PCB had said that its participation in the ODI World Cup would be subject to government approval. What was the reply of ICC to PCB? - ICC issued a statement and then replied to PCB. Regarding the situation in Pakistan, he said, "Pakistan has signed an agreement to participate in the World Cup. We are hoping that he will not renege on this agreement and will come to India. All the teams participating in the World Cup are bound by the rules and regulations of their country and we respect that as well. However, we are confident that Pakistan will definitely come to India to play the World Cup. Not allowed to play in the cup. The Government of Pakistan has started an inquiry into the security arrangements. According to reports, in the first week of July, the Pakistan government will take a decision on whether their team will go to India to play the ODI World Cup or not. Pakistan last played the T20 World Cup in India in 2016. The ICC Keep in mind in this matter- ICC has not given hosting of any match of Pakistan to Mumbai. Along with this, while deciding the venue of the semi-finals, PCB was also taken care of. The semi-finals will be played in Mumbai and Kolkata. However, the ICC issued a directive that if the Pakistan team reached the semi-finals, it would play its matches in Kolkata. On the other hand, if there is a semi-final match between India and Pakistan, then India will have to face Pakistan in Kolkata itself. Despite this, the drama of the Pakistan Cricket Board continues. Pakistan's ODI World Cup Schedule in 2023 - The Pakistan team will start their campaign on October 6 against the Qualifier-1 team. The qualifiers teams will be decided after the ongoing ODI World Cup qualifiers in Zimbabwe. Pakistan has to play two matches in Hyderabad, one in Ahmedabad, two in Bengaluru, two in Chennai and two in Kolkata. A total of 10 teams will participate in this World Cup. Eight teams have already qualified for the tournament and the remaining two places are being played in Zimbabwe with a qualifier round, with six teams making it to the Super Sixes. Two of these teams will participate in the main round of the World Cup to be held in India. World Cup matches will be played in 10 cities - World Cup matches will be played in 10 cities of India. There are matches in Hyderabad, Ahmedabad, Dharamshala, Delhi, Chennai, Lucknow, Pune, Bengaluru, Mumbai and Kolkata. Apart from Hyderabad, Guwahati and Thiruvananthapuram will host warm-up matches from September 29 to October 3. In this World Cup, all the teams will play in round robin format along with the other nine teams. Out of these, the top four teams in the points table will qualify for the semi-finals and the winning teams will compete in the finals. Last time the World Cup was organized in England in the same format. Then the English team defeated New Zealand in the final.

Fantasy gaming platform Dream-11 becomes Team India's lead sponsor, replaces Byju's

Now Dream-11 will be seen written on the jersey of the Indian team instead of Baiju. Recently Adidas became the new kit sponsor of the Indian cricket team. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has announced the new lead sponsor of Team India. Fantasy gaming platform Dream-XI will be the new sponsor of the Indian team. He replaced Byju. The BCCI announced this on Saturday. Now Dream-11 will be seen written on the jersey of the Indian team instead of Baiju. Recently adidas became the new kit sponsor of the Indian cricket team. A three-year agreement has been signed between Dream-11 and BCCI. However, the amount of this agreement has not been disclosed yet. Dream-11 will be seen written on Team India's jersey in the Test series starting against the West Indies. Team India's new World Cup cycle will start from here. Byju's contract ended this financial year. India's tour of the West Indies Team India will play a total of eight matches within a month on the West Indies tour. During this, the team will play a two-match Test series from July 12, whose first match will be played at the Windsor Park Sports Stadium in Dominica from July 12 to 16. At the same time, the three-match ODI series will start from 27 July. The five-match T20 series between India and West Indies will begin on August 3. What did BCCI President Roger Binny say? On the deal with Byju's, BCCI President Roger Binny said, "I congratulate Dream11 and appreciate their presence on the board. Welcome again From being the official sponsor of BCCI to now being the main sponsor, the partnership between BCCI and Dream11 has only gone from strength to strength. This is a direct testimony to the belief, value, potential and growth that Indian cricket has to offer. As we prepare to host the ICC World Cup later this year, enhancing the fan experience is one of our top priorities. I am confident that this partnership will help us connect with fans and enhance their experience.

What did the Co-Founder of Dream Sports say? Harsh Jain, Co-Founder and CEO of Dream Sports said, "Dream 11 is thrilled to take its partnership with the BCCI and Team India to the next level. At Dream11, we share our love for cricket with one billion Indian cricket fans and we are proud and privileged to be the lead sponsor of the national team.

Will Kohli play his last World Cup this time? Virat's 'special friend' gave this answer

Virat was in the Indian team that won the World Cup in 2011. Then his age was 23 years. Kohli was also a member of the team that reached the semi-finals in 2015. Mahendra Singh Dhoni was the captain at that time. After this, in 2019, under his captaincy, Team India lost in the semi-finals. India is going to host the ODI World Cup after 12 years. Last time in 2011, it organized the tournament together with Sri Lanka and Bangladesh. This will be the first time that India will host the tournament alone. This will be India's legendary batsman Virat Kohli's fourth World Cup. It is believed that he will be seen in this tournament for the last time. When his special friend Chris Gayle of West Indies was asked about this, he flatly refused. Gayle believes that Virat can play another World Cup after this. Virat was in the Indian team that won the World Cup in 2011. Then his age was 23 years. Kohli was also a member of the team that reached the semi-finals in 2015. Mahendra Singh Dhoni was the captain at that time. After this, in 2019, under his captaincy, Team India lost in the semi-finals. Kohli will enter the World Cup this time as the only active member of the team that won the title in 2011. What did Chris Gayle say? Kohli will be playing his fourth World Cup and Gayle feels the star batsman has the potential to play another World Cup. Gayle said in an interview, "Virat Kohli still has one more World Cup. I don't think this will be his last World Cup." Speaking on the hosts' chances in the World Cup, Gayle said that India are always favorites to win, especially when they are playing at home. Gayle said, "India is a contender to win the tournament. He is also playing at home this time. This time the tournament is going to be very interesting. We really want to see the team they are going to pick. First of all they are going to select the team as many people are knocking the door too. India will always be a contender at home. It also puts pressure on the Indian team. """""" India will play first match against Australia - India will start their campaign against Australia on October 8 in Chennai. He will play against Pakistan on October 15 in Ahmedabad. The tournament will begin on October 5 with the match between England and New Zealand. At the same time, the final will be played on 19 November. Both the opening and final matches will be played in Ahmedabad only.

After watching the story of Satyaprem, Karan shook hands with Karthik, the actor's fans gave this reaction

Karthik Aryan and Kiara Advani's most awaited film 'Satyaprem Ki Katha' has hit the theatres. His film is very much liked by the audience. Meanwhile, well-known filmmaker Karan Johar of B-Town arrived to watch Kiara and Karthik's film. Yes, recently Karan

Johar reached there with Maheep Kapoor in Mumbai. The filmmaker and the actor shook hands and interacted with each other, the video of which is becoming increasingly viral on social media. Sharing the video, a user wrote, "KJo went to watch SPKK and met Kartik as well .", following which the actor's fans also shared their thoughts on Karan Johar's recent interaction with him. One user wrote, "Haters are always secret admirers." Another wrote, "Keep your friends closer and your enemies closer." Another wrote, "Why does this feel so weird yet so good?" Another wrote, "He probably went to see Kiara Advani." In fact, Kartik Aaryan and Karan Johar had a fight last year and the filmmaker even replaced the actor from a film. Earlier, Karan Johar had announced that he would reshoot 'Dostana 2' after shooting a few scenes with Kartik. Responding to this, the actor said in an interview, "It happens sometimes. I haven't talked about this before. I believe in what my mother has taught me and it is also my values... When there is a fight between two people, the younger one should never speak about it. I follow him and that's why I never speak about it. 'Let us tell you that Karthik Aryan and Kiara Advani are in the story of Satyaprem, directed by Sameer Vidwans. The film is opening to positive reviews from the audience and the film also stars Gajraj Rao, Rajpal Yadav and Supriya Pathak in pivotal roles.

When Saif Ali Khan refused to dance with girls in night club, he was punched in the face

When Saif Ali Khan was in a nightclub in Delhi, he refused to dance with two girls, after which he had a fierce scuffle in the club. Known to keep He often talks openly about his

controversies. One such controversy happened when it was reported that the actor was involved in a fight with two men at a nightclub in the 1990s. Saif had clarified about the incident in an old interview that he had not started the fight. He revealed how the matter escalated so much that he was finally attacked. Saif Ali Khan told in an interview to Leharen.com that it was unfortunate that we had a fight. After the premiere of Main Khiladi Tu Anari, I went to a night club with my friends. I was approached by two girls asking me to dance with them. It went on like this for some time. After some time I asked him to leave us alone. The girls were at the club with their boyfriends. I told him to take care of the girls as we did not want to talk to anyone at that time. They didn't like it. He said you have a million dollar face and I am going to ruin it and then he punched me. Saif also revealed that his co-actress Mamta Kulkarni was not with him. When asked why he didn't file a police complaint, the actor said, "I didn't file a complaint because I didn't want any publicity on that matter, but if people blame me for the fight, I always understood." I can tell what went wrong. Talking about Saif Ali Khan's film career, the actor recently starred in the film 'Adipurush' alongside Prabhas and Kriti Sanon, in which he played the role of the villain 'Lankesh'. However, the film received negative reviews for its dialogues and poor portrayal of deities. The film's director Om Raut and dialogue writer Manoj Muntashir were also trolled a lot.

These actresses became Indira Gandhi before Kangana, showed the character of former Prime Minister on screen

Bollywood actress Kangana Ranaut is in discussion these days about her upcoming film Emergency. After the release of the film's teaser, his look in the film, his body language and dialogues have raised the curiosity of the fans about the film. It is believed that Emergency will prove to be Kangana's best performance. But do you know that even before Queen Kangna of B-Town, many actresses have played the role of former Prime Minister of the country Indira Gandhi on screen, today we will talk about the same actresses… Lara Dutta – Akshay Kumar in the year 2021 And Lara Dutta was seen in the role of Indira Gandhi in Vani Kapoor's film 'Bell Bottom'. His look was also discussed a lot in this film. The actress looked so perfect in this look that it was difficult to even recognize her.

Suchitra Sen - Suchitra Sen was seen in the role of a female politician in Sanjeev Kumar's film 'Aandhi' released in the year 1975. That character was being linked to former Prime Minister Indira Gandhi. Kishori Shahane - In Vivek Oberoi's film 'PM Narendra Modi',

famous TV actress Kishori Shahane played the role of Indira Gandhi. Flora Jacob - Kangana Ranaut's film Flora Jacob played the role of Indira Gandhi in Thalaivi. He also played this role in the film Raid. Avantika Akerkar- Avantika Akerkar played the role of former PM Indira Gandhi in the film 'Thackeray'. The character of Indira ji is a challenging task in itself, which Avantika played very well. Played the role of Due to his strong character, he had made a lot of headlines.